

न्यायालय अति जिला कलक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 14/2014

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
श्री सीमेन्ट लि ब्यावर जरिये वरिष्ठ प्रबंधक (विधि) एवं पॉवर एटार्नी हॉल्डर, श्री कमलकिशोर शर्मा जरिये पॉवर ऑफ अटोनी होल्डर ब्यावर, जिला अजमेर		1. माणकचन्द पुत्र पोककरराम जाति मेघवाल निवासी प्लॉट नं. 84, श्री गोपाल नगर, मसूदा रोड़, ब्यावर 2. मोडाराम पुत्र हीराराम 3. रूपाराम पुत्र गुलाब 4. गणपतलाल पुत्र गुलाब 5. गेपरराम पुत्र मोहन 6. हनुमान पुत्र मोहन 7. भीखाराम पुत्र मोहन 8. हेमराज पुत्र मोहन 9. बिदामी पत्नी मोहन जातिगण बावरी निवासीगण बुटीवास 10. प्रेमचन्द कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया जाति भांबी निवासी 49-सी 13, अंधेरी देवरी, तहसील मसूदा जिला अजमेर 11. नितिन भाटी पुत्र सुन्दरलाल जाति धोबी निवासी 17, नवरंग नगर, ब्यावर 12. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा बाबरा 13. एम.जी.बी. बैंक, शाखा गिरी 14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-

श्री पवन रांकावत, अधिवक्ता प्रार्थी  
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :- 24/8/2014

प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को खान एवं भू विज्ञान विभाग ने लीज प्रदान की है, जो दिनांक 14.11.1996 को लीजडीड निष्पादित की है, समय समय पर रिन्यूअल होती है। उक्त लीज वर्तमान में कार्यशील है। लीजडीड के अनुसार प्रार्थी को लीज क्षेत्र के आस-पास विभिन्न गांवों में भी अवस्थित भूमि, जिनके खसरा नम्बर पृथक पृथक है, के खातेदारान से अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु

अति. जिला कलक्टर, पाली



प्रक्रियाधीन है। ग्राम बुटीवास के खसरा नम्बर 468 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है, जो प्रार्थी के लीज क्षेत्र के समीप स्थित है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन कार्य करने हेतु उक्त भूमि का समनुषंगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी ईकाई अपने उद्योग को नहीं चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई का प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की उक्त खातेदारी भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी ईकाई तत्पर है। अतः उपरोक्त भूमि का मुआवजा निर्धारित करावे एवं भूमि प्रार्थी ईकाई को समनुषंगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध करवावे।

उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी को माईनिंग लीज प्राप्त है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी की माईनिंग लीज में स्थित है, जिसकी डी0एल0सी0 दर 59,280/- रूपये प्रति बीघा है एवं प्रश्नगत भूमि नगरपालिका क्षेत्र से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तहसीलदार रायपुर की मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजियात पर किसी प्रकार के पेड पौधो अथवा संरचना निर्मित नहीं है। खनन के अन्य समनुषंगी कार्य हेतु प्रार्थी को उक्त भूमि की आवश्यकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 (4) के अनुसार खनिज सम्पदा के दोहन से यदि किसी व्यक्ति के अधिकारो का उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति को सुना जाकर राज्य सरकार या उसका अभिहस्तांकिती ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के उल्लंघन के लिये प्रतिकर देगा एवं ऐसे प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार इस न्यायालय द्वारा राजस्थान भू अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रवधानों के अनुसार किया जाना है। राजस्व (ग्रुप 6) विभाग अधिसूचना क्रमांक पं.1 (3) राज- 6/2011/पार्ट/14 दिनांक 16.10.14 के अनुसार, प्राइवेट कम्पनी द्वारा भूमि अर्जन करने की स्थिति में पुनर्वासन और पुर्ववस्थान के प्रावधान लागू करने के लिए अवाप्ति भू क्षेत्र की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 हेक्टर तथा शहरी क्षेत्र में 200 हैक्टेयर है। प्रार्थी कम्पनी का अवाप्ति क्षेत्र उक्त सीमा से कम होने से उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं। भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध मे नया भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 दिनांक 1 जनवरी 2014 से लागू होकर, उनके प्रावधानों के अनुसार ही भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया एवं भूस्वामियों को दिये जाने वाले मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। चूँकि राज्य सरकार की ओर से भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध मे अलग से कोई भूमि अवाप्ति अधिनियम लागू नहीं किया गया है, अतः प्रकरण मे नए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। नये भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार अनुसूचि प्रथम में भूमि धारको को प्रतिकर के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके क्रम संख्या 1 से 6 के अन्तर्गत कुल प्रतिकर की गणना किस प्रकार की जायेगी, का क्रमवार उल्लेख किया गया है एवं उक्त अनुसूचि की क्रम संख्या 2 के अनुसार दिये जाने वाले प्रतिकर के कारको 1 से 2, जो कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट की दूरी पर आधारित होगा, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जावे, क्रम संख्या 4 में भूमि से जुडी हुई सम्पत्तियो के निर्धारण एवं क्रम संख्या 5 में तोषण का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा, का उल्लेख किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रार्थी कम्पनी द्वारा धारित भूमि के सम्बन्ध में सूचना चाहे जाने पर प्रार्थी कम्पनी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा धारित भूमि कम्पनी एक्ट को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान



कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम के तहत अधिशेष योग्य नहीं है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)राज-6/2011/पार्ट/14 दिनांक 16.10.2014 के पश्चात प्रार्थी ईकाई द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में एक हजार हैक्टेयर से कम भूमि अर्जित की गई है। प्रार्थी ईकाई द्वारा इस अधिनियम से पूर्व अवाप्त, आवंटित, क्रय की गई भूमि पर यह नियम लागू नहीं होता है। प्रार्थी ईकाई द्वारा राज्य सरकार के समय समय पर निर्मित कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना की जा रही है। प्रार्थी ईकाई द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 के तहत आवेदित भूमि का प्रार्थी ईकाई के पक्ष में सरफेस राईट प्रदान किया जाता है व अप्रार्थी को न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित मुआवजा राशि प्रार्थी ईकाई द्वारा अदा की जाती है। भूमि का स्वामित्व अप्रार्थी से राज्य सरकार में निहित हो जाता है। प्रार्थी ईकाई अप्रार्थी को न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है। अतः प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित कराने का निवेदन किया।

तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की दूरी निकटतम नगरपालिका क्षेत्र से 45 कि.मी. है एवं उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना क्रमांक प01(3)राज. 6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.06.2016 में उल्लेखित भूमि का गुणक, जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावेगा, वह 2.00 है तथा गुणित किये गये उक्त बाजार मूल्य में एकट की अनुसूचि के प्रावधानों के अनुसार पेड़ पौधों व संपत्ति की कीमत को जोडा जाना है एवं धारा 30(1) के अनुसार ऐसी राशि की शत प्रतिशत तोषण की राशि होगी। प्रार्थी को राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु पट्टा 50 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया गया है, जिसके सहायक कार्य हेतु प्रश्नगत भूमि चाही जाने से इस भूमि के खातेदार के सरफेस राईट का उल्लंघन होगा। जिसके लिये अप्रार्थी को प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना आज्ञापक है। अप्रार्थी ने अपने जवाब में ही नियमानुसार मुआवजा भुगतान करने पर उक्त भूमि प्रार्थी कम्पनी के उपयोगार्थ दिये जाने हेतु सहमति जाहिर की है। अतः प्रतिकर का निर्धारण निम्नानुसार सारणी के अनुरूप किया जाता है -

	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	डी.एल. सी.दर	राशि (कॉलम संख्या 3 x 5)	नगर पालिका से दूरी व गुणक		कुल राशि (कॉलम संख्या 6 x 8) रु.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	माणकचन्द पुत्र पोककराम कौम मेघवाल, प्लॉट नं. 84, गोपाल नगर, मसूदा रोड़ ब्यावर 1/6, प्रेमचन्द कुचेरिया पुत्र चेनाराम कुचेरिया कौम भांबी, सा0 सी0 13 मण्डोली बांगडनगर, अंधेरी देवरी, तहसील मसूदा 7/12, मोडराम पुत्र हीराराम कौम बावरी निवासी बुटीवास 1/24, रूपाराम पुत्र गुलाब कौम बावरी निवासी बुटीवास 1/24, गणपतलाल पुत्र गुलाब कौम बावरी नि0 बुटीवास 1/24, गेपरराम, हडमानराम, भीकाराम, हेमराज पि0 मोहन, विदामी पत्नी मोहन 1/24 खातेदार	468	22.02 बीघा	बा0अ0	59280	1304160	40	2.00	2608320
B	योग								2608320



C	प्रभावित भूमि पर अवस्थित पेड़ों की मालियत	25000
D	अन्य संरचना	0.00
E	योग (कॉलम संख्या B + C + D )	2633320
F	तोषण 100 प्रतिशत ( कॉलम E के समान राशि )	2633320
G	कुल देय प्रतिकर राशि ( E + F )	5266640

अतः प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त मुआवजा राशि रुपये 52,66,640/- (अक्षरे बावन लाख छियासठ हजार छह सौ चालीस रूपए मात्र) अप्रार्थी के नाम का चैक बनाकर तहसीलदार रायपुर को एक माह की अवधि में उपलब्ध करावे। तहसीलदार रायपुर माफिक आदेशानुसार सम्बन्धित राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। अपील अवधि गुजरने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में भूमि बिलानाम (सिवायचक) माईनिंग लीज अंकित की जावें। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का उपयोग प्रार्थी इकाई को लीज अवधि तक प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89(2) में वर्णित माईनिंग से संबंधित समनुषंगी कार्यों (Subsidiary Purposes) के लिए ही करने का अधिकार होगा। भविष्य में राज्य सरकार अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि भुगतान में संशोधन किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अन्तर राशि की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायपुर/प्रार्थी कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।



(भागीरथ बिश्नोई)  
अति.जिला कलेक्टर पाली

निर्णय आज दिनांक 20/8/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)  
अति.जिला कलेक्टर पाली

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/8/18	वजुलाय 3401 <del>इस</del> पत्रिका प्रार्थी को वरुस सुनी गई। पत्रिका वास्ते मि.दि. 24.8.2018 को पेश हो। जति. जिला कलेक्टर, पाली	
24.8.2018	वजुलाय 3401 <del>इस</del> पत्रिका आज वास्ते निरयि पेश हुई विस्तृत निरयि पृथक से लिखया जाकर वाद हस्त कर शांमिं किया गया। निरयि अनुसार <del>प्र</del> प्र.प स्वीकार किया जाता है। माफिक निरयि पालना होकर पत्रिका वाद पालना फेरल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। जति. जिला कलेक्टर, पाली	
24.8.2018	वजुलाय 3401 पत्रिका का अवलोकन किया। प्रकरण में पारित आदेश दि. 24.8.2018 के पेज सं. 3 में वर्णित प्रतिकर निवारण की सारणी में अप्रार्थ सं. 11 का नाम दर्ज होने से छूट गया है। जिसे दर्ज किया जाना विधि समत है। अतः CPC की धारा 152 के तहत उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश दि. 24.8.2018 के पेज सं. 3 में वर्णित प्रतिकर निवारण की सारणी में फेरल सं. 1 में दर्ज प्रविक्रियों को वदस्तूर ररते हुए, उनके साथ नितिन श्रीश. सुन्दरलाल जाति छोटी नि. 17, नवरंग नगर, व्यावसायिक व ससा जादी तदनुसार आदेश की पालना की जाने वाद पालना पत्रिका फेरल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। जति. जिला कलेक्टर, पाली	